DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY : It is a shameless reply... *(Interruption)*...

MR. CHAIRMAN : Q. No. 282.

SHRI VASANT SATHE: I object to this, Sir, I beg your pardon.

The hon. Member uttered just now a word "shameless reply".

I am very sorry, Sir. Please admonish the hon. Member.

MR. CHAIRMAN Please see that these words are not used.

DR. G. VIJAYAMOHAN REDDY : That is all right, Sir.

मध्य प्रदेश में सीमेंट के उत्पादन में कमी

*282. **श्री अजीत जोगी :**

कुमारी ईदा खातून :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के सीमेन्ट-कारखानों में उनकी पूर्ण क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसमें कमी का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस राज्य में सीमेंट-उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किन-किन कदमों पर विचार किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) 1988–89 के दौरान मध्य प्रदेश में सीमेंट संयंत्रों ने बड़े क्षेत्र में निम्नलिखित क्षमता उपयोग प्राप्त किया जिसकी पिछली अवधि के दौरान भारतीय सीमेंट उद्योग द्वारा प्राप्त किए गए 77% के स्तर से अनुकूल दृष्टि से तुलनीय है :–

सरकारी क्षेत्र	74%
गैर-सरकारी क्षेत्र	96%
कुल	94%

अप्रैल-जुलाई, 1989 की अवधि के दौरान, राज्य में सरकारी क्षेत्र के सीमेंट संयंत्र 85% क्षमता उपयोग प्राप्त कर सके हैं ।

(ग) मौजूदा अधिष्ठापित क्षमता का इष्टतम उपयोग एक सतत प्रक्रिया है और अवस्थापना संबंधी निविष्टियों की उपलब्धता में वृद्धि करके, रख-रखाव के उन्नत तरीके अपनाकर, आधुनिकीकरण इत्यादि द्वारा इस दिशा में निरन्तर प्रयास किए जाते हैं ।

श्री अजीत जोगी : सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर पटल पर रखा है उसके अनुसार मध्य प्रदेश की सीमेंट की इकाइयों में सरकारी क्षेत्र में केवल 74 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा है जब कि इसके विपरीत गैर-सरकारी क्षेत्र में अर्थात् प्राइवेट सेक्टर में 96 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा है । इन दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि पब्लिक सेक्टर की जो सीमेंट की इकाइयां हैं उनकी क्षमता का उपयोग बढ़ रहा है, इस उत्तर में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि सरकारी क्षेत्र की क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए कोई कारगर उपाय किये जा रहे हैं । इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा कि विशेष रूप से ऐसे कौन से कदम उठाये गये हैं जिससे सरकारी क्षेत्र की सीमेंट की इकाइयों का आधुनिकीकरण हो सके, विशेषकर जो आजकल ड्राई प्रोसेसिंग और प्रीकेल-सीनेशन की टेक्नालोजी का उपयोग सभी निजी क्षेत्रों की इकाइयों में किया जा रहा है तो उनको क्या सरकारी क्षेत्रों की इकाइयों में भी करेंगे ? उसी तरह से इलेक्ट्रानिक पैकेजिंग की जो पद्धति निजी क्षेत्रों में लागू है, क्या उसको सरकारी क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा ? जो क्षमता कम है, आधुनिक सीमेंट ईकाई में चार हजार टन प्रति दिन की क्षमता को दक्ष क्षमता योग्य माना गया है तो क्या जो हमारी

सरकारी क्षेत्र की ईकाइयां मध्य प्रदेश में है उनकी क्षमता चार हजार टन प्रति दिन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जाएंगे ? इन तीनों विषयों में यानी ड्राई प्रासेसिंग, प्री-केलसीनेशन टेक्नोलोजी और इलेक्ट्रोनिक पैकेजिंग यूनिटस और चार हजार टन केपेसिटी के विषय में क्या कदम उठाये गये हैं, इनका मैं उत्तर प्राप्त करना चाहता हूं ।

SHRI J. VENGAL RAO : We are taking care of these public sector units also. According to the current year targets, the capacity increase is 85 percent.

श्री **अजीत जोगी** : श्रीमन्, मैंने तीन टेक्नोलोजी के विषय में पूछा है उनके बारे में मंत्री महोदय ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया है । निजी क्षेत्रों में तीन टेक्नोलोजीज का उपयोग हो रहा है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में नहीं हो रहा है । इसीलिए सरकारी क्षेत्र में क्षमता इतनी कम है । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकारी क्षेत्र में ही इन तीनों टेक्नोलोजीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसके कारण निजी क्षेत्र की क्षमता इतनी ही पावर सप्लाई में और वैसे ही रा-मेटिरियल में 96% रही है ? आपकी क्षमता आपके उत्तर के अनुसार 74 प्रतिशत रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन तीनों टेक्नोलाजी को इंट्रोड्यूस करने के लिये आप कदम उठायेंगे, इस विषय में मंत्री जी स्पेसिफिक उत्तर देने की कृपा करें ।

SHRI J. VENGAL RAO : Sir, some of the units are old ones. We are modernising them with the latest technology. We will certainly maximise the production. (*Interruption*).

MR. CHAIRMAN : .... with modernisation, he will take care of that.

श्री **अजीत जोगी** : मेरा उत्तर नहीं आया मान्यवर ।

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : He wants to know what the technologies are.

श्री **अजीत जोगी** : आप इतना बता दें कि आप तीनों टेक्नोलाजी को सरकारी क्षेत्र में इंट्रोड्यूस करेंगे ?

श्री **सभापति** : इसको करेंगे ऐसा कैसे कह देंगे । दूसरा सप्लीमेंटरी कीजिये ।

SHRI J. VENGAL RAO : Sir, the capacity approved for the implementation of various States including Madhya Pradesh is up to 400 million tonnes. We are going ahead.

श्री **अजीत जोगी** : मान्यवर, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में सीमेंट का उत्पादन राष्ट्र में 45 मिलियन टन रहा है । वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह बढ़कर आठवीं पंचवर्षीय योजना में 65 मिलियन टन हो जायेगा अर्थात् करीब 16 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता बढ़ानी होगी । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इस क्षमता को बढ़ाने के लिये क्या नये प्लांट लगाये जायेंगे ? इन नये प्लांटों में से कितने प्लांट मध्य प्रदेश में लगाये जायेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसका कच्चा माल बहुतायत में मिलता है। मैं यह भी जानना चाहूंगा, जैसा कि अभी तक हुआ है सरकारी क्षेत्र के प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया है, तो क्या नया प्लांट लगने पर मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों को वहां पर रोजगार देने में प्राथमिकता दी जायेगी ?

SHRI J. VENGAL RAO : In Madhya Pradesh, Sir, the production is 111 lakh tonnes. (*Interruptions*). One-fourth of the production of the country is from Madhya Pradesh only. For private sector also we granted a new letter of intent. In Rewa, to Jaiprakash Industries we recently granted one million tonnes. Two more plants are coming up. Madhya Pradesh is at the top of the list.

SHRI AJIT P.K. JOGI : M question related to the Eighth Five Year Plan. I wanted to know whe ther during the Eighth Five-Year Plan, since your requirement would be 65 million tonnes as against the present capacity....(*Interruption*). Would you go in for new plants ?

श्री सभापति : उन्होंने कहा है कि सैक्शन किया है ।

SHRI J. VENGAL RAO : Sir, this year's target was only 45 million tonnes. We reached 50 million tonnes.

MR. CHAIRMAN : Very good.

SHRI J. VENGAL RAO: We are asking cement manufacturers to try to export to other countries. We will reach the Eighth Five-Year Plan target also.

MR. CHAIRMAN : Very good.

SHRI G. SWAMINATHAN : Sir, this answer seems to be very confusing. The answer says, public sector—74 per ent.

MR. CHAIRMAN : The question is about Madhya Pradesh.

SHRI G. SWAMINATHAN : The answer says, public sector-74 per cent; private sector-96 per cent and overall-94 per cent.

MR. CHAIRMAN : It is about Madhya Pradesh.

SHRI J. VENGAL RAO : It is about Madhya Pradesh, not the entire country.

MR. CHAIRMAN : Please read the question. Your supplementary is to the question, not to the reply. Shri Ram Naresh Yadav.

SHRI G. SWAMINATHAN : It is about Madhya Pradesh cement... (*Interruption*).

MR. CHAIRMAN : It is about Madhya Pradesh only. He has said about Madhya Pradesh only.

SHRI G. SWAMINATHAN : This is the answer given.

MR. CHAIRMAN : Supplementary arises from the question and the answer is also addressed to the question. Shri Ram Naresh Yadav.

श्री राम नरेश यादव : मान्यवर माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि पब्लिक सेक्टर में सार्वजनिक उद्योगों में मध्य प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन 74 प्रतिशत होता है और निजी क्षेत्र में यह 96 प्रतिशत होता है । इतना बड़ा अन्तर इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि सचमुच में हमारा पब्लिक सेक्टर कमजोर जा रहा है । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन से कारण हैं, कौन से फैक्टर्ज हैं जिनके आधार पर इतना बड़ा अन्तर सार्वजनिक क्षेत्र के सीमेंट उद्योग में मध्य प्रदेश में है और उन कारणों को आने वाले दिनों में कितने वर्षों में सरकार दूर कर सकेगी ताकि प्राइवेट सेक्टर में जितना उत्पादन होता है उतना उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में भी हो सके ।

SHRI J. VENGAL RAO : Sir, there are three public sector units in Madhya Pradesh. The first unit at Akaltara is producing 67 per cent. The second unit at Manjhar is producing 100 per cent. The third unit at Neemuch is producing 89 per cent. I submit to you, Sir, that all these plants will produce more quantity of cement with modernisation.

श्री सैयद सिब्ते रजी : मान्यवर, अभी जोगी साहब के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें नये कदम उठाये जा रहे हैं वह क्या नये कदम हैं जिसका जवाब (सी) में कहा गया है कि

"augmenting availability of infrasturctural inputs, introduction of improved methods of maintenance, modernisation, etc."

जोगी जी ने जो सवाल पूछा था उसका मंत्री जी ने जवाब यह दिया कि हम उसको देखेंगे और जायजा लेंगे वह तो जवाब आ गया लेकिन सवाल यह है कि जो आपने अब तक कार्यवाही की है माडर्नाइजेशन के सिलसिले में मेंटेनेंस की नयी तकनीक लगाने के सिलसिले में और इनफास्ट्रक्चर इनपुटस की अवेलेबिलिटी बढ़ाने में तो उसके क्या आंकड़े हैं। आप पिछले तीन वर्ष के नहीं तो कम से कम पिछले एक वर्ष के आंकड़े आप बता दीजिये कि आपने पब्लिक सेक्टर में जो फैक्टरीज लगाई हुई हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए उनको प्राइवेट सेक्टर के बराबर लाने के लिए क्या किया है ?

SHRI J. VENGAL RAO : Sir, the question is about Madhya Pradesh.

MR. CHAIRMAN : His question is about Madhya Pradesh.

SHRI M. ARUNACHALAM : Sir the Cement Corporation has taken steps for improving the performance of all these three factories in Madhya Pradesh. Time-bound preventive maintenance has been planned and is being implemented. Unit management has been re-organised and strengthened. Sir, an action plan has also been prepared. As my senior colleague has just now mentioned, the performance of these three units has improved a lot between April and July.

SHRI G. SWAMINATHAN: Sir, I have to ask...

MR. CHAIRMAN : You come to my Chamber. I have ruled that it is out. It is not a supplementary arising out of this question. I have said it with all the responsibility.

Price control on Vitamins

*283. CHOWDHARY RAM SEWAK :
DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI :

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 137 given in the Rajya Sabha on the 24th April 1989 and state :

(a) whether Vitamin-A has now been price controlled and if so, what steps have been taken to fix its price ;

(b) whether it is also a fact that this Ministry has left out Vitamins outside the purview of price control and singled out only Vitamin A ; and

(c) if so, what steps have been taken to bring all bulk Vitamins under price control?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Vitamin-A has been brought under price control since 18th November, 1988. As per the provisions of DPCO, 1987, the prices of bulk drug/formulations prevailing on 18-11-1988 stand frozen. However, the ceiling prices of formulations under DPCO, 1987 are under Notification. The bulk drug price will be notified after receipt of recommendation from the BICP based on their fresh cost-cum-technical study.

(b) Vitamin-A and Vitamin-C have been brought under price control.

(c) No such step is contemplated.